छः क्षेत्रीय रेलों पर दंडित किये गये रेल कर्मचारियों की संख्या वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान क्रमशः 14, 37 और 42 थी। तीन क्षेत्रीय रेलों पर, इस सम्बन्ध में दंडित किये गये कर्मचारियों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी हां। माल डिब्बों के असम्बद्ध हो जाने तथा उन्हें गलत स्थान को प्रेषित कर दिये जाने की घटनाओं को न होने देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) ये हिदायतें फिर दुहरा दी गई हैं कि माल डिब्बों के लेबलों को नीली पेंसिल से साफ-साफ लिखा जाये और प्रेषक और गन्तव्य स्थानों के नाम बड़े अक्षरों में साफ-साफ लिखा जाय।

(2) रेलों को हिदायतें दी गई हैं कि जब तक उसी स्थान को बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या 20 से अधिक हो जावे तो प्रेषक और गन्तव्य स्थानों के नाम लेबुलों पर छपवा कर दिये जायें।

(3) रेलों से इस बात की पक्की व्यवस्था करने को कहा गया कि बन्द माल डिब्बों के दरवाजों पर अन्दर की ओर चेप वाले लेबुल चिपकायें और खुले मालडिब्बों के दोनों दरवाजों के हत्थों के साथ बांधे जाने वाले लेबुल लगायें।

(4) रेलों से कहा गया है कि कोयला और इस्पात से लदे हुए खुले मालडिब्बों के सोलबारों पर एक अतिरिक्त लेबुल चिपकायें।

(5) ये हिदायतें फिर से दे दी गयीं हैं कि मालडिब्बों के साथ लेबुल फीते से बांधे जायें, सुतली से नहीं।

(6) खुले माल डिब्बों के लिए मालडिब्बा लेबुल होल्डर का एक नयी डिजाइन विकसित किया जा रहा है जिससे मालडिब्बे के बाहर से लेबुल न हटाया जा सके।

(7) रेलों को हिदायत दी गयी है कि मार्क करने और लेबुल लगाने सम्बन्धी हिदायतों का पूरा पूरा अनुपालन किया जाता है या नहीं—यह देखने के लिए वे जब-तब निरीक्षण करें।

पेट्रोल के भाव बढ़ने से पेट्रोल पम्पों का बन्द होना

5269. **श्री लालजी भाई : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पेट्रोल के भाव बढ़ने के बाद सारे देश में 30 प्रतिशत पेट्रोल पम्प अब तक बन्द हो चुके हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।

ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान को आर्थिक सहायता

5270. **श्री लालजी भाई : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1969 के दौरान हुए भारत-अमरीका एक समझौते के अनुसरण में अमेरिका भारत को ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 105 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में किश्तों में दे रहा है।

(ख) क्या इस अनुदान की 15.17 करोड़ रुपये की अन्तिम किश्त हाल ही में भारत को दी गयी है ;

(ग) इस धनराशि में से कितनी राशि राजस्थान के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) इस अनुदान के उपयोग संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को भारत सरकार द्वारा दी गई धनराशियों और अनुदानों में से ऋण दिये जाते हैं। अतः यह कहना संभव नहीं कि अमेरिका से प्राप्त केवल अनुदान अंश से राजस्थान को ग्राम विद्युतीकरण के

लिए कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है। बहरहाल, निगम ने अभी तक राजस्थान बिजली बोर्ड की 39 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं जिसमें 2203 ग्रामों के विद्युतीकरण और 45941 पम्पों के ऊर्जन के लिए 19.79 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है। इस स्कीमों को 3-5 वर्षों की अवधि में पूर्ण करने की योजना बनायी गई है।

Construction of Nangal-Talwara Railway Line

5271. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken about the sanction and construction of new Railway Lines surveyed in the Calender year 1972;

(b) if so, whether the case of Nangal-Talwara Railway Line has been finally decided; and

(c) the likely date by which the construction work for the new Railway Line would be started?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, in some cases.

(b) Not yet.

(c) Does not arise.

Assurance to Bhakra Dam oustees by the Minister of Irrigation and Power

5272. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Government have followed up the assurances given to Bhakra Dam Oustees by Dr. K. L. Rao, the then Minister for Irrigation and Power, at a public meeting at Bhakra as also in the meeting with the Legislators of the Bilaspur District (H.P.) on 21st October, 1973;

(b) if so, the assurances given by him in brief; and

(c) whether any official machinery would be set up by the Central Government to expedite the implementation of these assurances and to co-ordinate the various schemes with the State Government of Himachal Pradesh?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c) There is no record of any assurance given by Dr. K. L. Rao during the meetings in question, except that he had observed that the problems of the Bhakra Oustees should be discussed with the concerned authorities of the Himachal Pradesh Government to assess their magnitude. The Government of Himachal Pradesh have, however, intimated that Dr. Rao had given some assurances, most of which involve the Bhakra Management Board. The matter is being examined. For the resettlement of Bhakra Dam oustees, agricultural land was acquired for them in Hissar District. Those who did not want to avail of this facility were paid full compensation for their lands and properties and were to be resettled outside the reservoir area by the Himachal Pradesh Government. As a special case, the Bhakra Management Board has provided drinking water supply and electricity to Bhakra and neighbouring villages. Medical facilities are also available to these people at the Board's Dispensary near Bhakra Dam and in the Canal Hospital at Nangal.

Employment to employees of B.S.L. project in H.P.

5273. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government are making alternative arrangements to ensure employment to the large number of skilled and Unskilled employees who would be rendered surplus with the completion of Beas, Satluj Link Project in Himachal Pradesh;